



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 1987/भाद्र 20, 1909

No. 458]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1987/BHADRA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 821(अ) :—भारत के संविधान की दसवीं  
अनुसूची के पैरा 6(1) के अन्तर्गत लोक सभा अध्यक्ष द्वारा  
9 सितम्बर, 1987 को दिया गया निम्नलिखित विनिश्चय  
एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

“कांग्रेस

श्री के.पी. उन्नीकुण्णन, लोक सभा सदस्य ने (जिन्हें  
उसमें उसके पश्चात अर्जीदार कहा गया है) संविधान की  
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 और लोक सभा सदस्य (दल  
परिवर्तन के आधार पर निर्णय) नियम, 1985 के नियम  
6 के अधीन 6 अर्थात्, 1987 को मधुसूदान मुदर्शन दास और  
वाहिदास पाटिल कोणनावकर (जिन्हें इसमें उनके पश्चात्  
प्रत्यर्थी कहा गया है) के विरुद्ध दो अलग-अलग अर्जियां दी  
थीं।

अर्जीदार द्वारा अपनी अर्जियों में लगाया गया मुख्य  
आरोप यह था कि प्रत्यर्थी जो कांग्रेस (एस) दल के टिकट/  
चिन्ह पर क्रमशः करीमगंज (असम) और औरंगाबाद (महा-  
राष्ट्र) निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा के लिये निर्वाचित  
हुए थे, के कांग्रेस (आई) दल में शामिल हो जाने के कारण  
संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के  
अनुसार सभा के सदस्य होने के लिये निर्ह हो गये हैं।  
अर्जीदार ने यह तर्क दिया था कि प्रारम्भ में कांग्रेस (एस)  
विगत दल के लोक सभा में चार सदस्य थे, अर्थात् सर्वश्री  
के.पी. उन्नीकुण्णन, बी. किशोर चन्द्र एस० देव, मुदर्शन  
दास और माहिब राव पाटिल कोणनावकर। इन चारों  
सदस्यों में से, दो सदस्य अर्थात् प्रत्यर्थियों ने कांग्रेस (आई)  
दल में प्रवेश पाने का अनुरोध किया और उन्हें कांग्रेस  
(आई) दल में शामिल कर लिया गया। अर्जीदार के अनुसार  
इन सदस्यों द्वारा कांग्रेस (एस) राजनीतिक दल जिसमें वे  
शुद्धतः सम्मिलित थे, की आत्मीय सदस्यता को स्वेच्छया छोड़ने  
का सामना बनता है। अर्जीदार ने यह तर्क भी दिया था

कि प्रत्यक्षियों के कांग्रेस (आई) दल में प्रवेश की संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4(1) के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिसमें यह उपबंध है कि "सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप पैरा (1) के अधीन उस दशा में निरहिता नहीं होगा जब उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है", कि ऐसे विलय के दैध होने के लिये पैरा 4(2) में अधिकृत गतें, अर्थात् "—यह तभी समझा जाएगा जब संविधान विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिये सहमत हो गये हों, पुरा नहीं की गई है। इसलिये, अजीदार ने प्रार्थना की थी कि प्रत्यक्षियों की सभा के सदस्य होने के लिये निरहित घोषित किया जाये।

लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 1985 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 7 (1) के अनुसार मेरा समाधान होने के बाद कि याचिकाएँ नियम 6 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, मैंने निदेश दिया कि याचिकाओं की प्रतियाँ प्रत्यक्षियों और कांग्रेस (आई) विधान दल के नेता को इन नियमों के नियम 7(1)(क) और (ख) के अनुसार उनकी टिप्पणियों के लिए प्रेषित की जाएँ।

प्रत्यक्षियों ने अपने गमान उत्तरों में बताया कि कांग्रेस (एम) दल श्री शरद पवार की अध्यक्षता वाला एक राष्ट्रीय दल है। अजीदार तथा कांग्रेस (एस) विधान दल के सदस्य, श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव को कांग्रेस (एम) कार्य-कारिणी समिति द्वारा 29 नवम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में दल की प्राथमिक सदस्यता में निष्कासन कर दिया गया। कांग्रेस (एस) दल के अध्यक्ष, श्री शरद पवार ने कार्य-कारिणी समिति के इस निर्णय की सूचना लोक सभा अध्यक्ष को 30 नवम्बर, 1986 को दी थी। बाद में कांग्रेस (एस) दल ने आन्गावाड में, 9 दिसम्बर, 1986 को हुए कांग्रेस (एस) के पूर्णाधिवेशन में कांग्रेस (आई) दल में अपने विलय का निर्णय किया। इस प्रकार, प्रत्यक्षियों के अनुसार, सर्वश्री के.पी. उन्नीकुण्णन तथा बी. किशोर चन्द्र एस. देव के कांग्रेस (एस) दल के प्राथमिक सदस्यता में निष्कासन के परिणामस्वरूप लोक सभा में कांग्रेस (एस) विधान दल की सदस्य संख्या कांग्रेस (एस) दल के कांग्रेस (आई) दल में विलय होने के समय केवल दो थी न कि चार, जैसा कि अजीदार द्वारा दावा किया गया है। अतः प्रत्यक्षियों ने दावा किया कि कांग्रेस (आई) दल में उनका प्रवेश वैध है और संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंध के अनुसार है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत), ने जिन्होंने कांग्रेस (आई) दल के नेता की ओर से उत्तर दिया—जो नियमों के नियम 3(1)(क) के अनुसार उनके लिए प्राधिकृत है, बताया कि लोक सभा में कांग्रेस (एम) विधान दल की सदस्य संख्या निम्नलिखित पहले चार थी, परन्तु सर्वश्री के.पी. उन्नीकुण्णन और बी. किशोर चन्द्र एस. देव के कांग्रेस (एस) दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन के पश्चात् लोक सभा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार उन्हें लोक सभा में असम्बद्ध सदस्य माना गया है। इसके परिणामस्वरूप लोक सभा में कांग्रेस (एस) विधान दल की सदस्य संख्या घटकर दो रह गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी बताया कि जब कांग्रेस (एस) दल के कांग्रेस (आई) दल में विलय के समय कांग्रेस (एम) विधान दल में केवल दो सदस्य (अर्थात् प्रत्यक्षी) ही थे, इसलिए कांग्रेस (आई) दल में उनका प्रवेश "पूर्णतया वैध", "विधिवत् ठीक" और संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4(2) के उपबंध के अनुसार है।

अजीदार ने 6 मई, 1987 को मुझे एक पत्र लिखा जिसमें दल के टिकट/चुनाव चिह्न पर निर्वाचित सदस्यों को असम्बद्ध घोषित करने के मेरे अधिकार पर आपत्ति करते हुए कुछ वैधानिक और संवैधानिक मुद्दे उठाए गए थे। अजीदार के अनुरोध पर मैंने उन्हें भारत के महान्यायवादी को उनकी राय जानने के लिए भेज दिया। दिनांक 20 जुलाई, 1987 को दी गई राय में भारत के महान्यायवादी ने बताया कि मेरे द्वारा की गई कार्यवाही "सही और विधि के अनुसार" है।

अतः यह स्पष्ट है कि अजीदार का यह तर्क कि प्रत्यक्षी लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरहित हो गए हैं, मान्य नहीं है। इसलिए, मेरा यह निर्णय है कि प्रत्यक्षियों का कांग्रेस (आई) दल में प्रवेश विधिमानी और विधि संगत है और वे लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरहित नहीं हुए हैं। इन अजियों में कोई तर्कसंगत आधार नहीं है और इन्हें नियमों के नियम 8(1)(क) के निबंधनों के अनुसार खारिज किया जाना आवश्यक है।

सामने के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा, निम्नलिखित विनिश्चय देता हूँ, घोषणा करता हूँ और आदेश देता हूँ—

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं,

बलराम जाखड़, अध्यक्ष, लोक सभा, पत्रद्वारा यह प्रस्ताव देता है कि श्री के.पी. उन्नीकृष्णन द्वारा सर्वश्री सुदर्शन दास और साहिबराव पाटिल डोंगांवकर के विरुद्ध 6 अप्रैल, 1987 को दी गई अज्ञिया में कोई तर्कवन्त आधार नहीं है और सर्वश्री सुदर्शन दास और साहिबराव पाटिल डोंगांवकर संबिधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के निबंधनों के अनुसार निर्दोष नहीं हुए हैं। तदनुसार, मैं इन अज्ञियों को खारिज करता हूँ।

बलराम जाखड़,

अध्यक्ष,

लोकसभा।”

नई दिल्ली :

दिनांक : 9 सितम्बर, 1987

18 भाद्र, 1909 (शक)

[सं. 28/1/86-टी]

सुभाष कश्यप, महासचिव।

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 9th September, 1987

### NOTIFICATION

S.O. 821(E).—The following decision dated the 9th September, 1987, of the Speaker, Lok Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

### “ORDER

Shri K. P. Unnikrishnan, member of Lok Sabha, (hereinafter called the petitioner) gave two separate petitions on 6th April, 1987, against Sarvashri Sudarshan Das and Sahabrao Patil Dongaonkar, members of Lok Sabha, (hereinafter called the respondents) under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution and rule 6 of the Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985.

The gravamen of the charges made by the petitioner in his petitions was that the respondents—who were elected to Lok Sabha on the ticket/symbol of Congress(S) Party from Karimganj (Assam) and Aurangabad (Maharashtra) constituencies respectively had incurred disqualification for being members of the House in terms of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution consequent upon their admission to the Congress(I) party. The petitioner had contended that originally there were four members of Congress(S) legislature party in Lok Sabha viz., Sarvashri K. P. Unnikrishnan, V. Kishore Chandra S. Deo, Sudarshan Das and Sahabrao Patil Dongaonkar. Out of these four members, two i.e., the respondents sought admission and were admitted to the Congress(I) party. According to the petitioner, this amounted to voluntarily giving up, by these members, their membership of Congress(S) political party to

which they originally belonged. The petitioner had also contended that the admission to respondents to the Congress(I) party was not protected by paragraph 4(1) of the Tenth Schedule to the Constitution which provides that “a member of a House shall not be disqualified under sub-paragraph (1) of paragraph 2 where his original political party merges with another political party”, since the conditions laid down in paragraph 4(2) for such a merger to be valid viz., “.....if, and only if, not less than two-thirds of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger”, had not been fulfilled. The petitioner had, therefore, prayed that the respondents be declared disqualified for being members of the House.

After having satisfied myself in terms of rule 7(1) of the Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985 (hereinafter called the Rules) that the petitions complied with the requirements of rule 6, I directed that copies of the petitions be forwarded to the respondents and the Leader of the Congress(I) legislature party in terms of rule 7(3)(a) and (b) of the Rules for furnishing their comments.

The respondents in their identical replies stated that the Congress (S) was a national party under the Presidentship of Shri Sharad Pawar. The petitioner and another member of Congress(S) legislature party, Shri V. Kishore Chandra S. Deo were expelled from the primary membership of the party by the Congress(S) Working Committee at its meeting held on 29th November, 1986. This decision of the Working Committee was conveyed to the Speaker, Lok Sabha on 30th November, 1986 by the President of Congress(S) party, Shri Sharad Pawar. The Congress(S) party later decided to merge with Congress(I) party at the Congress(S) Plenary Session held at Aurangabad on 9th December, 1986. Thus, according to the respondents, consequent upon the expulsion of Sarvashri K. P. Unnikrishnan and V. Kishore Chandra S. Deo from the primary membership of the Congress(S) party, the strength of the Congress(S) legislature party in Lok Sabha, at the time of merger of Congress(S) party with Congress(I) party was only two and not four as contended by the petitioner. The respondents, therefore, claimed that their admission to the Congress(I) party was valid and within the provisions of paragraph 4 of the Tenth Schedule to the Constitution.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri H. K. L. Bhagat) who replied on behalf of the Leader of the Congress(I) Party—being so authorised in terms of rule 3(1)(a) of the Rules—stated that the strength of the Congress(S) legislature party in Lok Sabha was no doubt originally four, but subsequent to the expulsion of Sarvashri K. P. Unnikrishnan and V. Kishore Chandra S. Deo from the primary membership of the Congress(S) party, they were treated as unattached members in the Lok Sabha as per the directions of the Speaker, Lok Sabha. The strength of the Congress(S) legislature party in Lok Sabha, consequently came down to two. The Minister of Parliamentary Affairs further stated that as the Congress(S) legislature party consisted of only two members (viz., the respondents) at the time of merger of Congress(S) party with Congress(I) party, their

admission to the Congress(I) party was 'perfectly valid', 'legally sound' and in accordance with the provision of paragraph 4(2) of the Tenth Schedule to the Constitution.

On 6th May, 1987, the petitioner addressed a letter to me raising certain legal and constitutional points questioning my authority to declare members elected on a party ticket/symbol as unattached. On the petitioner's request, I referred these to the Attorney General for India for his opinion. In his opinion dated 20th July, 1987, the Attorney General for India stated that the action taken by me was "correct and in accordance with law".

It is thus obvious that the contention of the petitioner that the respondents have become disqualified for being members of Lok Sabha is untenable. I, therefore, hold that the admission of the respondents to the Congress(I) party is valid and legal and they have not incurred any disqualification for being members of Lok Sabha. The petitions have no merit and need to be dismissed in terms of rule 8(1)(a) of the Rules.

Taking into account all the facts and circumstances of the case and in accordance with the provisions of

the Tenth Schedule to the Constitution, I hereby decide, declare and order as follows :—

In exercise of powers conferred upon me under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, I, B. R. JAKHAR, Speaker, Lok Sabha, hereby decide that the petitions dated 6th April, 1987, given by Shri K. P. Unnikrishnan against Sarvashri Sudarshan Das and Sahabrao Patil Dongaonkar have no merit and Sarvashri Sudarshan Das and Sahabrao Patil Dongaonkar have not incurred any disqualification in terms of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution. I accordingly dismiss the petitions.

B. R. JAKHAR

Speaker,

NEW DELHI :

Dated : 9th September, 1987.

Lok Sabha."

[No. 28/1/86-T]

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary-General.